www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 206 | जौनपुर शनिवार, 14 मार्च 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

वैश्विक संकट से निपटने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहा भारत : पीएम नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के खिलाफ इजरायल–अमेरिका की संयुक्त लड़ाई के बाद आए वैश्विक संकट को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संकट से निपटने में भारत कोई कोर–कसर नहीं छोड़ रहा है। पीएम मोदी ने आज शुक्रवार को सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, "आज युद्ध के चलते जो वैश्विक संकट बना है, उससे निपटने में भारत कोई कोर–कसर नहीं छोड़ रहा है।" वीडियो में पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, "आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो

रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद तो एक्सपोज हो ही रहे हैं और देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम या अधिक मात्रा में हर कोई शिकार है। भारत सरकार भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। हम अलग–अलग स्तरों पर प्रयास कर रहे हैं। बीते दिनों दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेताओं से मेरी इसको लेकर बातचीत हुई है। सप्लाई चेन में जो बाधाएं आई हैं, उनसे हम कैसे पार पाएं, इसके लिए भी निरंतर प्रयास चल रहे हैं।" पीएम मोदी ने कहा, "इस वैश्विक संकट ने एक बार फिर दिखाया है कि किसी भी देश का आत्मनिर्भर होना इतना अधिक जरूरी क्यों है। इसलिए ही बीते वर्षों में हमने भारत को एनर्जी सेक्टर्स में आत्मनिर्भर बनाने के लिए होलिस्टिक तरीके से काम किया है।"

लखनऊ पहुंचे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, ग्रीन कॉरिडोर का किया लोकार्पण

लखनऊ, संवाददाता। लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर का शुक्रवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लोकार्पण किया। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे जनता को समर्पित किया। झूलेलाल पार्क में लोकार्पण समारोह हुआ। यूपी सरकार के कई मंत्री और भाजपा पदाधिकारी भी इसमें शामिल हैं। यह ग्रीन कॉरिडोर कुल 57 किलोमीटर लंबा है। ग्रीन कॉरिडोर के चलते निशातगंज, डालीगंज, समतामूलक, बादशाहनगर और आसपास के इलाकों में जाम की समस्या काफी हद तक खत्म होगी। भारी ट्रैफिक अब गोमती किनारे बने इस कॉरिडोर से सीधे निकल सकेगा, जिससे अंदरूनी सड़कों पर दबाव कम होगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से गुरुवार को मुलाकात की। एक घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान अखिलेश जमीन पर बैठे नजर आए। बाहर निकलने पर अखिलेश ने मीडियाकर्मियों से कहा– शंकराचार्य से मिलकर आ रहा हूं।

समस्या का जल्द समाधान निकालना चाहिए : शशि थरूर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। देशभर में एलपीजी गैस की कमी वाली खबरों को लेकर सियासत तेज है। आरोप–प्रत्यारोप की राजनीति के बीच इस मामले की गूंज शुक्रवार को संसद तक सुनाई दी। ऐसे में अब इन खबरों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय के बयान के अनुसार पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की सप्लाई पर्याप्त है, लेकिन ऐसा लगता है कि एलपीजी की सप्लाई में कुछ कमी हो रही है। थरूर ने इस बात पर जोर दिया कि इस कमी का ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एलपीजी में कमी के चलते खासकर ग्रामीण इलाकों में लोग अब लकड़ी और कोयले की जगह गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसे में अगर सिलेंडर आसानी से नहीं मिलते, तो यह लोगों के लिए बड़ी समस्या बन जाती है। इस दौरान थरूर ने देशवासियों को एकजुट रहने का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में देश को एकजुट होकर इस समस्या का जल्द समाधान निकालना चाहिए, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। एलपीजी की कमी वाली खबरों के बाद थरूर ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इस्राइल की तरफ से ईरान पर हमला करना गलत था। उनके मुताबिक उस समय बातचीत चल रही थी और ईरान कई मांगों को मानने के लिए तैयार दिखाई दे रहा था,।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को केंद्र की बड़ी राहत, 1,912.99 करोड़ रुपए की मंजूरी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राहत देने के लिए बड़ी आर्थिक सहायता की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की बैठक में कुल 1,912.99 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है। यह सहायता आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर को दी जाएगी। सरकार के अनुसार यह मदद वर्ष 2025 के दौरान आई प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़, फ्लैश फ्लड, क्लाउडबर्स्ट, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान चक्रवात मोंथा से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास और राहत कार्यों के लिए दी जा रही है। उच्च

स्तरीय समिति के फैसले के मुताबिक राज्यों को अलग–अलग राशि स्वीकृत की गई है। इसमें आंध्र प्रदेश को 341.48 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपए, गुजरात को 778.67 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश को 288.39 करोड़ रुपए, नागालैंड को 158.41 करोड़ रुपए और जम्मू–कश्मीर को 330.34 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। यह पूरी राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से दी जा रही है। हालांकि इसमें संबंधित राज्यों के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में मौजूद शुरुआती बैलेंस के 50 प्रतिशत को समायोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अतिरिक्त सहायता पहले से जारी फंड के अलावा है। यानी राज्यों को पहले से जो राशि एसडीआरएफ के तहत उपलब्ध कराई गई थी, उसके ऊपर यह नई आर्थिक मदद दी जा रही है। केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है ।

बांग्लादेश में डेढ़ साल में अल्पसंख्यकों पर 3100 हमले, संसद में सरकार का खुलासा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर भारत की संसद में बड़ा खुलासा हुआ है। केंद्र सरकार ने बताया कि अगस्त 2024 से फरवरी 2026 के बीच हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ लगभग 3100 हिंसक घटनाएं दर्ज की गई हैं। यह जानकारी मानवाधिकार संगठनों के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर दी गई है। सरकार का कहना है कि वह इन घटनाओं पर लगातार नजर बनाए हुए है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के घरों, दुकानों, धार्मिक स्थलों और संपत्तियों पर हमलों की घटनाएं सामने आई हैं। भारत सरकार ने इन मामलों को कई बार बांग्लादेश सरकार

के सामने उठाया है। सरकार का कहना है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत लगातार अपनी चिंता व्यक्त करता रहा है। सरकार के अनुसार मानवाधिकार संगठनों के आंकड़ों में अगस्त 2024 से फरवरी 2026 के बीच लगभग 3100 हिंसक घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन घटनाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के घरों और संपत्तियों पर हमले, आगजनी और तोड़फोड़ शामिल हैं। इसके अलावा कई धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आई हैं। विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने इस मुद्दे को कई स्तरों पर उठाया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ होने वाली बैठकों और वार्ताओं में भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का विषय उठाया गया है। भारत ने उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश सरकार इन घटनाओं की पूरी जांच करेगी और दोषियों को सजा दिलाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश के सभी नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां की सरकार की है। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय भी शामिल हैं। भारत का मानना है कि बांग्लादेश सरकार को इन घटनाओं को गंभीरता से लेकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

पंजाब सरकार एलपीजी आपूर्ति पर नजर रख रही है : भगवंत मान

चंडीगढ़, (एजेंसी)। खाड़ी क्षेत्र में जारी युद्ध और एलपीजी सिलेंडरों की संभावित कमी की अफवाहों के मद्देनजर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है ताकि लोगों को आवश्यक वस्तुओं तक पहुंचने में कोई कठिनाई न हो। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसी भी परिस्थिति में घबराहट, जमाखोरी या उपभोक्ताओं के शोषण को बर्दाश्त नहीं करेगी।मुख्यमंत्री मान ने कहा कि खाड़ी देशों में तनाव के कारण पूरे भारत में एलपीजी की संभावित कमी की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं, जिससे जनता में अनावश्यक चिंता पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में युद्ध के कारण एलपीजी सिलेंडरों की कमी की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पंजाब सरकार पूरी तरह सतर्क है और स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी न हो और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।हालात का फायदा उठाने की कोशिशों के खिलाफ चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में दहशत फैलाने या हेरफेर करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री मान ने जोर देकर कहा कि यदि कोई भी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करके या कमी की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी या अधिक कीमत वसूलना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अधिकारियों को बाजार पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई भी एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी में शामिल पाया जाता है ।

गैस सिलेंडर के लिए सुबह से ही उपभोक्ताओं की लग रही लंबी कतारें,गैस के अभाव मे होटल के संचालक मिट्टी के चूल्हे व भट्टी का कर रहे उपयोग

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। अमेरिका–ईरान युद्ध के बीच घरेलू व कमर्शियल गैस सिलेंडर पर संकट शहर से लेकर गांव तक दिखाई दे रहा है।इस समय सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है जिनके घरों पर सिलेंडर कुछ ही दिनों के लिए शेष बचा हुआ है और उन लोगों के सामने और समस्या है जिनके घरों पर सिलेंडर खत्म हो गया है।इसके साथ ही साथ शहर के कई रेस्टोरेंट,होटल, कैंटीन,ठेलों वालों के लिए भी यह समस्या गंभीर बनी हुई है।इन प्रतिष्ठानों का संचालन करने वाले कई संचालकों का यह भी मानना है कि कमर्शियल सिलेंडर के न उपलब्ध होने से अधिकतर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों व अन्य गैस उपभोक्ता पुरानी परंपरा मिट्टी से निर्मित चूल्हे का उपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।मिट्टी के चूल्हे अंगूठी भट्टी का उपयोग होटल रेस्टोरेंट ढाबों सहित अन्य गैस उपभोक्ताओं द्वारा किए जाने के चलते कोयल तथा लड़कियों के साथ–साथ लकड़ी के गुटखों का भी दाम आसमान छूने लगा है।वही गैस एजेंसी ऊपर लंबी भीड़ देखी गई।गैस की किल्लत से आम लोगों का किचन भी प्रभावित हो रहा है।गैस एजेंसी पर पहुंचे पुरुष और महिला ग्राहकों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई।उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले से महंगाई से परेशान गरीबों पर और बोझ डाला जा रहा है।कई लोगों ने कहा कि रसोई चलाना अब और मुश्किल हो जाएगा।वही गैस बुकिंग के नियम भी बदल गये है।जब गैस उपभोक्ता सिलेंडर लेने के लिए अपने–अपने संबंधित गैस एजेंसियों के पास पहुंचे तो वहां पर कर्मियों द्वारा यह बताया गया कि अभी सिलेंडर नहीं है।जबकि कुछ गैस उपभोक्ताओं ने यह भी कहा कि शासन के ढुलमुल रही रवैया के चलते और अचानक घरेलू व कामर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में अत्यधिक बढ़ोतरी के चलते गैस एजेंटीयों ने अपने–अपने यहां सिलेंडरों को डंप कर लिया है और यहां तक की ब्लैक में भी सिलेंडर बेच रहे है। गैस उपभोक्ताओं का मानना है कि आने वाले वर्ष 2027 की विधानसभा चुनाव में इसका गंभीर परिणाम शासन को भुगतना पड़ेगा।मंगलवार को गैस सिलेंडर उपभोक्ता कई एजेंसियों प गैस सिलेंडर लाने के लिए गए लेकिन वहां पर उन्हें निराशा ही मिली।कमर्शियल गैस सिलेंडर न मिलने के चलते शहर के कई बड़े होटल रेस्टोरेंट, ढाबों के संचालक काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं।बताते चले कि सिविल लाइंस के होटल शाने अवध, होटल तिरुपति और अवंतिका रेस्टोरेंट व अन्य ने विकल्प तलाशना शुरू किया।गैस की कमी के कारण भोजन बनाने के लिए पारंपरिक और वैकल्पिक साधनों का सहारा लिया जा रहा है।कई होटलों में लकड़ी के चूल्हे और मिट्टी के पारंपरिक चूल्हे फिर से इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं।कुछ स्थानों पर कोयले की भट्टी बनाकर भोजन तैयार किया जा रहा है।बड़े होटलों में बिजली से चलने वाले इंडक्शन चूल्हों का भी उपयोग शुरू हो गया है।श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के कारण होटल–रेस्टोरेंट पर भोजन व्यवस्था का दबाव बढ़ा।होटल स्टाफ की बड़ी संख्या के लिए भी भोजन बनाना चुनौती बन गया है।वैकल्पिक साधनों से किसी तरह नाश्ता और खाना तैयार किया जा रहा है।होटल संचालकों ने सरकार से जल्द कमर्शियल गैस आपूर्ति बहाल करने की मांग की है।

संक्षिप्त खबरें

वाराणसी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित करवाने का प्रयास

नई दिल्ली, (एजेंसी)। वाराणसी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित करवाने संबंधी प्रस्ताव को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। सरकार से यह मांग राज्यसभा में की गई। शुक्रवार को राज्यसभा में कहा गया कि वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन और लगातार बसे शहरों में से एक है। यहां के प्राचीन मंदिर, पौराणिक गंगा के घाट और सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपराएं इसे अद्वितीय बनाती हैं। यहां का संगीत, कला और स्थापत्य विश्वभर में प्रसिद्ध है और इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। भाजपा के राज्यसभा सांसद संजय सेठ ने शुक्रवार को राज्यसभा में यह विषय रखते हुए कहा कि वह आज पूरे सदन और देश का ध्यान भगवान शिव की नगरी काशी, अर्थात् वाराणसी की पर्यटन क्षमता और सांस्कृतिक विरासत की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले ग्यारह वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में वाराणसी ने विकास की एक महत्वपूर्ण यात्रा तय की है। 2014 से पहले यह शहर गंदगी, टूटी सड़कों और बिजली के उलझे तारों की समस्या से जूझ रहा था, लेकिन आज यह तेजी से एक आधुनिक और वैश्विक शहर के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी अनेक यात्राओं के दौरान अपनी इस कर्मभूमि को 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी है। चाहे वह काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण हो, घाटों का पुनर्निर्माण हो या सड़कों का चौड़ीकरण, हर जगह विकास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

बिहार के पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने नागालैंड के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली

कोहिमा, (एजेंसी)। बिहार के पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने शुक्रवार को नागालैंड के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने कोहिमा के लोक भवन में आयोजित सादे समारोह में यादव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफिउ रियो, उपमुख्यमंत्री यांथुगो पैटन और टीआर जेलियांग, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य और सुरक्षा व सैन्य अधिकारी समारोह में उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मुख्य सचिव सेंटियांगर इम्चेन ने किया। मुख्यमंत्री नेफिउ रियो ने नंदकिशोर यादव को नागालैंड के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने पर बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 मार्च को छह राज्यों व दो केंद्रशासित प्रदेशों में राज्यपालों और उपराज्यपालों की नियुक्ति और तबादलों की घोषणा की थी। फेरबदल के तहत बिहार के पूर्व मंत्री व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उन्होंने अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया है, जो 25 अगस्त से मणिपुर के राज्यपाल के रूप में कार्यरत रहते हुए।

संपादकीय

नई व्यवस्था बनने की आशाएं धूमिल

नेताओं के अवसरवाद तथा आर्थिक समस्याओं से त्रस्त नौजवानों ने कुछ नया बनाने की इच्छा के साथ तत्कालीन सरकार को उखाड़ फेंका था। लेकिन उसके बाद अब लोगों के पास जो विकल्प हैं, उनसे नई व्यवस्था बनने की आशाएं धूमिल ही हैं। पिछले साल सितंबर में हुए जेन–जी विद्रोह से नेपाल में आया बदलाव कितना टिकाऊ साबित हुआ, यह गुरुवार को होने वाले मतदान के परिणाम से जाहिर होगा। नेपाल के एक करोड़ 90 लाख मतदाता 275 सदस्यों की प्रतिनिधि सभा को चुनने के लिए मतदान करेंगे। नेपाल की चुनाव प्रणाली के मुताबिक 165 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत चुने जाते हैं। बाकी 110 सीटें विभिन्न पार्टियों को उन्हें मिले मत प्रतिशत के अनुपात में आवंटित की जाती हैं। जेन–जी विद्रोह का प्रमुख कारण राजनीतिक दलों की सत्ता लिप्सा, वर्षों से जारी उनका अवसरवाद, और राजनेताओं के परिजनों की आलीशान जिंदगी थी। बेरोजगारी तथा आर्थिक समस्याओं से त्रस्त नौजवानों ने कुछ नया बनाने की इच्छा के साथ तत्कालीन सरकार को हिंसक ढंग से उखाड़ फेंका। लेकिन विडंबना यह है कि उसके बाद अब लोगों के पास जो विकल्प हैं, उनसे नई व्यवस्था बनने की आशाएं धूमिल ही हैं। लोगों के सामने नए विकल्प के तौर पर उज्यालो नेपाल पार्टी अकेला नया दल है, लेकिन उसकी संभावनाएं ज्यादा उज्ज्वल नहीं मानी जा रही हैं। नयेपन का अहसास कराने वाला एक अन्य दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) है, जिसका उदय पिछले संसदीय चुनाव के समय हुआ था। रैपर और काठमांडू के बहुचर्चित मेयर बालेन शाह इसी दल में शामिल होकर प्रधानमंत्री के दावेदार के बतौर चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें जेन–जी का प्रिय उम्मीदवार बताया गया है। बाकी विकल्प वही पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूएमएल), नेपाली कांग्रेस, और कई कम्युनिस्ट गुटों के विलय से पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के नेतृत्व में बनी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी हैं। पारंपरिक समर्थन आधार और चुनाव मशीनरी के लिहाज से ये तीनों पार्टियां अभी भी मजबूती के साथ मैदान में हैं। वैसे युवाओं के समर्थन से आरएसपी जीत की ओर बढ़ सकती है। मगर यह पार्टी किसी बुनियादी परिवर्तन का माध्यम बनेगी, अपने कार्यक्रम एवं चुनाव घोषणापत्र से ऐसी कोई उम्मीद वह नहीं जगा पाई है। यानी नेपाल में किसी गुणात्मक परिवर्तन के संकेत कम ही हैं। मात्रात्मक बदलाव भी आएगा, इसकी उम्मीद बहुत बलवान नहीं है।

युद्ध के बावजूद ईरान की हवा साफ, मगर शांति के बावजूद दिल्ली

नीरज

पश्चिम एशिया इस समय युद्ध की आग में झुलस रहा है। लेबनान, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और इजराइल के कई इलाकों में मिसाइल हमले और बमबारी जारी हैं। कई शहरों के ऊपर तेल और धुएं के काले गुबार उठते दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि इन युद्ध प्रभावित इलाकों की हवा भारत के कई प्रमुख शहरों से कहीं ज्यादा साफ है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई के आंकड़े बताते हैं कि युद्ध क्षेत्र में भी हवा का स्तर दिल्ली और मुंबई जैसे भारतीय महानगरों से बेहतर बना हुआ है। 11 मार्च 2026 को भारतीय समयानुसार शाम चार बजे वायु गुणवत्ता मंच एक्यूआई डाट इन के आंकड़ों के अनुसार तेहरान का एक्यूआई लगभग 33 दर्ज किया गया, जबकि उसी समय दिल्ली का एक्यूआई 63 था। दिन के दौरान भी स्थिति इसी तरह रही। दोपहर बारह बजे तेहरान का अधिकतम एक्यूआई 47 रहा, जो अच्छे स्तर में आता है। इसके विपरीत दिल्ली में सुबह आठ बजे एक्यूआई 323 तक पहुंच गया, जो अत्यंत खराब श्रेणी में आता है। यह स्थिति तब है जब तेहरान और आसपास के क्षेत्रों में तेल भंडार और ऊर्जा ढांचे पर हमलों के कारण धुएं और जहरीली गैसों की आशंका बनी हुई है। सोशल मीडिया पर आठ मार्च की रात तेहरान के ऊपर काले धुएं के घने बादल दिखने के दृश्य सामने आए थे। यहां तक कि कुछ इलाकों में काली वर्षा की भी खबरें आईं, जो तेल भंडार में लगी आग और रासायनिक धुएं का परिणाम मानी जा रही हैं। लोगों ने गले में जलन और आंखों में खुजली की शिकायत की, और प्रशासन ने नागरिकों को घर के भीतर रहने की सलाह दी। इसके बावजूद वास्तविक समय के आंकड़े बताते हैं कि तेहरान में एक्यूआई अधिकतर समय शून्य से पचास के बीच यानी स्वस्थ श्रेणी में बना रहा। यह तथ्य भारतीय शहरों की वायु गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है क्योंकि भारत के कई महानगरों में वायु प्रदूषण लगातार खराब, बहुत खराब या गंभीर श्रेणी में रहता है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में प्रदूषण की समस्या मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से पैदा होती है। सबसे बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। तेजी से बढ़ती निजी गाड़ियों की संख्या नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूक्ष्म कणों को बढ़ाती है। यही वजह है कि दिल्ली के साथ–साथ बेंगलुरु, हैदराबाद और लखनऊ जैसे शहर भी समय समय पर खराब हवा से जूझते रहते हैं। इसके अलावा निर्माण कार्य से उठने वाली धूल, उद्योगों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाले धुएं तथा ईंट भट्ठों से उत्सर्जित गैसें भी प्रदूषण को बढ़ाती हैं। डीजल जनरेटर से निकलने वाला धुआं और सड़कों की धूल इस समस्या को और गंभीर बनाते हैं। ग्रामीण इलाकों में खाना पकाने के लिए लकड़ी, गोबर और जैव ईंधन जलाने से भी हवा में प्रदूषण बढ़ता है। उत्तर भारत में एक और महत्वपूर्ण कारण खेतों में पराली जलाना है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलने से धुआं बड़ी मात्रा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक पहुंचता है और सर्दियों में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब कर देता है। भौगोलिक स्थिति भी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाती है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक तरह के निचले बेसिन में स्थित है। इसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार हैं। इस कारण प्रदूषक तत्व यहां फंस जाते हैं और आसानी से बाहर नहीं निकल पाते। साथ ही उत्तर पश्चिम से बलूचिस्तान और थार मरुस्थल की ओर से आने वाली धूल भी प्रदूषण को बढ़ाती है। इसके विपरीत तेहरान, तेल अवीव, बेरूत और दुबई जैसे कई पश्चिम एशियाई शहर समुद्र के नजदीक स्थित हैं या ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां हवाएं प्रदूषकों को तेजी से फैलाकर साफ कर देती हैं। समुद्र के किनारे होने के कारण हवा का प्रवाह बेहतर रहता है और प्रदूषण का जमाव कम होता है। वहीं मुंबई समुद्र किनारे होने के बावजूद प्रदूषण से जूझता है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका मुख्य कारण स्थानीय स्रोत हैं, खासकर वाहनों की अत्यधिक संख्या। मुंबई में वाहनों का घनत्व कई शहरों की तुलना में कई गुना ज्यादा है, इसलिए यहां प्रदूषण का स्तर भी ऊंचा बना रहता है। इसके अलावा, युद्ध से होने वाला प्रदूषण भी एक अलग प्रकृति का होता है। बमबारी या आग लगने से भारी मात्रा में धुआं और जहरीली गैसें

निकलती हैं, लेकिन यह प्रदूषण अक्सर अस्थायी होता है। जब आग बुझ जाती है या घटना समाप्त हो जाती है तो उस स्रोत से निकलने वाला प्रदूषण भी रुक जाता है। इसके विपरीत वाहनों, उद्योगों और निर्माण कार्य से निकलने वाला धुआं लगातार हवा में जाता रहता है, जिससे लंबे समय तक प्रदूषण बना रहता है। हम आपको यह भी बता दें कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हाल के दिनों में दिखाई दी गई स्मॉग को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं कि यह ईरान में तेल रिफाइनरी पर हमलों से जुड़ी हो सकती है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह स्मॉग दरअसल पश्चिमी हवाओं के साथ आई मरुस्थलीय धूल का परिणाम है। हम आपको बता दें कि पांच से सात मार्च के बीच बलूचिस्तान और मध्य पाकिस्तान से चली तेज पश्चिमी हवाएं राजस्थान के थार मरुस्थल से होकर गुजरीं और बड़ी मात्रा में धूल को उत्तर पश्चिम भारत तक ले आईं। हवा में तैरते ये धूल कण आकाश को धूसर और भूरा बना देते हैं और दृश्यता कम कर देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान में हुए विस्फोटों का प्रदूषण भारत तक पहुंचने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि दोनों क्षेत्रों के बीच लगभग ढाई से तीन हजार किलोमीटर की दूरी है। इतनी लंबी दूरी तय करते समय प्रदूषक तत्व काफी कमजोर हो जाते हैं। देखा जाये तो वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों के फेफड़ों के विकास पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। एक हालिया वैश्विक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में लगभग सत्रह लाख अठारह हजार लोगों की मौत वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के कारण हुई। युद्ध क्षेत्र में उठने वाला धुआं भले ही डरावना दिखाई दे, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार भारत के शहरों में फैला स्थायी प्रदूषण कहीं ज्यादा खतरनाक है। यह धीरे धीरे लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और एक तरह से अदृश्य हत्यारा बन जाता है। बहरहाल, इस पूरी स्थिति से एक स्पष्ट संदेश मिलता है कि भारत में प्रदूषण से निपटने के लिए वाहनों के उत्सर्जन, उद्योगों के धुएं, निर्माण धूल और पराली जलाने जैसी समस्याओं पर सख्त नियंत्रण जरूरी है। जब तक इन स्रोतों को प्रभावी तरीके से नियंत्रित नहीं किया जाएगा, तब तक देश के शहरों में स्वच्छ हवा का सपना अधूरा ही रहेगा।

निवारक स्वास्थ्य देखभाल में अग्रणी भूमिका निभा रहा है योग

प्रतापराव जाधव द्वारा

बीते दशक में योग को केवल पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति के रूप में ही नहीं सराहा गया, बल्कि उसे उत्त रोत्तवर रूप से स्वास्थ्य और कल्याण के लिए साक्ष्य–आधारित दृष्टिकोण के रूप में भी पहचाना जाने लगा है। वैज्ञानिक अनुसंधान, डिजिटल नवाचार और वैश्विक सहयोग अब हमें योग को केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत ही नहीं, बल्कि एक सशक्तै जन–स्वास्थ्य हस्तक्षेप समझने में भी मदद कर रहे हैं। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था न (एमडीएनआईवाई) को पारंपरिक चिकित्सा (योग) के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया है और योग अनुसंधान में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका और भी मजबूती प्रदान करते हुए वर्ष 2025–2029 के लिए इसे फिर से निमित किया गया है। यह पहचान गैर–संचारी रोग (एनसीडी) के लिए साक्ष्य–आधारित योग हस्तिक्षेपों को बढ़ावा देने में संस्था न की बढ़ती भूमिका को दिखाती है। इस पहल के प्रमुख साझेदारों में आयुष मंत्रालय, एम्सा दिल्ली, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, दिल्ली शामिल हैं। इन सहयोगों के माध्यम से केंद्र मधुमेह, मोटापा और तनाव से संबंधित विकारों जैसे गैर–संचारी रोगों के लिए योग–आधारित हस्तक्षेपों पर तकनीकी दिशानिर्देश विकसित कर रहा है और अनुसंधान को आगे बढ़ा रहा है। इन प्रयासों में अंतरराष्ट्रीय संगठन भी साझेदारी कर रहे हैं, जिससे योग की वैज्ञानिक आधारशिला और मजबूत हो रही है तथा निवारक स्वास्थ्य देखभाल के लिए व्यापक रूप से लागू किए जा सकने वाले, किफायती और साक्ष्य–समर्थित प्रभावी साधन के तौर पर योग की क्षमता प्रदर्शित हो रही है। संस्थागत स्तर पर एमडीएनआईवाई योग की वैज्ञानिक आधारशिला को मजबूती प्रदान करना जारी रखे हुए है। शरीर क्रिया विज्ञान, जैव रसायन, बायोमैकेनिक्स और मनोविज्ञान की अनुसंधान प्रयोगशालाओं के माध्यम से यह संस्थान योग के मनो–शारीरिक और जैव–रासायनिक प्रभावों, उम्र बढ़ने में इसकी भूमिका तथा जीवनशैली से जुड़े विकारों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करता है। यह कार्य पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ जोड़ने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है डिजिटल प्लेरटफॉर्मों ने योग की पहुँच को और अधिक बढ़ाया है, जिससे साक्ष्य–आधारित पद्धतियाँ सीधे लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन रही हैं। एम–योग मोबाइल एप्लिकेशन और वाई–ब्रेक प्रोटोकॉल जैसे प्रयास यह दिखाते हैं कि योग की प्रामाणिकता और चिकित्सकीय महत्वि बनाए रखते हुए उसे बड़े स्तर पर पहुँचाया जा सकता है। विश्वै स्वास्स्य् च संगठन के सहयोग से विकसित किए गए एम–योग प्लेटफॉर्म पर 1.1 लाख से अधिक डाउनलोड दर्ज किए जा चुके हैं, जो सुलभ डिजिटल वेलनेस टूल्स में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। वहीं कार्यस्थल योग कार्यक्रम वाई–ब्रेक कृ जो काम के दौरान 5–10 मिनट का सरल योग ब्रेक है कृ से अब तक 33 लाख से अधिक सरकारी अधिकारियों को लाभ मिल चुका है। इन पहलों से प्राप्त अनुसंधान निष्कर्ष और सहभागिता विश्लेषण अत्यंत उत्साहजनक हैं। वाई–ब्रेक अभ्यास से कुछ ही सप्ताहों में अनुभूत तनाव में लगभग 40 प्रतिशत तक कमी देखी गई है। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि इससे मानसिक सतर्कता, भावनात्मक दृढ़ता और निर्णय–क्षमता में सुधार होता है। इसके साथ–साथ कॉर्टिसोल स्तर जैसे शारीरिक संकेतकों में भी सकारात्मक परिवर्तन पाए गए हैं। शारीरिक लाभों में गर्दन, कंधे और कमर के दर्द में कमी, श्वास अभ्यास से सांस लेने की क्षमता में सुधार और संपूर्ण जीवन शक्ति में वृद्धि शामिल हैंकृये परिणाम विशेषकर आज के निष्क्रिय, स्क्रीन–आधारित कार्यस्थलों में प्रासंगिक हैं। वाई–ब्रेक अभ्यास ने अनुपस्थिति में कमी लाने , कर्मचारियों के मनोबल में सुधार लाने, और कार्य–जीवन में स्वस्थ संतुलन कायम करने में भी योगदान दिया है, जो व्यक्तिगत और संगठनात्मक कल्याण दोनों को मजबूत बनाने की योग की क्षमता को दर्शाता है। एमडीएनआईवाई और केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा सम्मेलन–2026 के दौरान भी वैज्ञानिक प्रमाण के महत्वो पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने यह रेखांकित किया कि सुदृढ़ अनुसंधान, अंतरविषयक सहयोग, और प्रभावी डिजिटल सहभागिता आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में योग को एकीकृत करने और स्प ष्टि स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हैं। ये घटनाक्रम योग के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। अब इसे केवल व्यक्तिगत कल्याण के अभ्यास के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि यह उत्ततरोत्तेर रूप से जन–स्वास्थ्य, कौशल विकास और वेलनेस आधारित रोजगार के अवसरों के एक मार्ग के रूप में उभर रहा है। योग परंपरा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ते हुए ग्लोबल योग क्रांति की प्रेरक शक्ति के रूप में उभर रहा है तथा अंतरराष्ट्रीय वेलनेस क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को और मजबूत कर रहा है। जैसे–जैसे हम 13 मार्च के करीब पहुँच रहे हैं, जो 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 100–दिन के काउंटडाउन का संकेत है।

तेल संकट के बीच पीएम मोदी ने चीन को दिया ऐसा ऑफर, चौंक गए ट्रंप

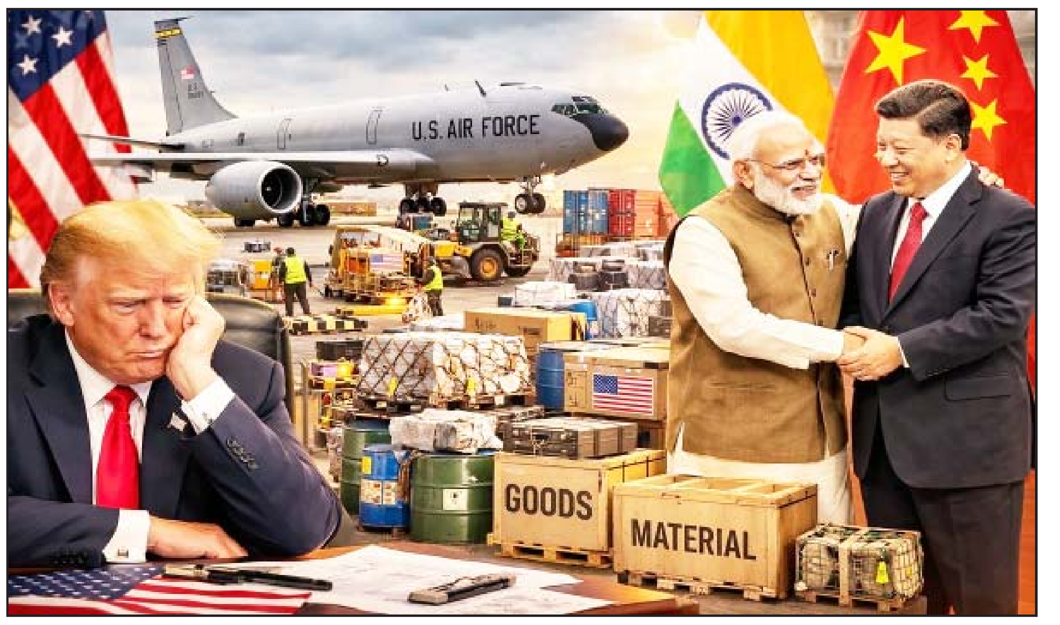

अभिनय

भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। सरकार ने चीन से आने वाले निवेश को लेकर कुछ शर्तों में ढील देने का फैसला किया है। यानी अब चीन की कंपनियों के लिए भारत में निवेश करना पहले से आसान हो सकता है। आपको बता दें सरकार का मानना है कि इससे देश में निवेश बढ़ेगा। रोजगार के नए अवसर बनेंगे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी। लेकिन इस फैसले को लेकर राजनीतिक और रणनीतिक बहस भी शुरू हो चुकी है। तो आखिर जानते हैं क्या है मोदी कैबिनेट का यह बड़ा फैसला। चीन को भारत में निवेश की अनुमति क्यों दी जा रही है? इससे भारत को फायदा होगा या खतरा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। इसके तहत, अप्रैल 2020 में बनी प्रेस नोट 3 (च्छ3) की व्यवस्था में बदलाव को मंजूरी दी गई। सरकारी बयान के मुताबिक, इससे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स और सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।श कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, पॉलीसिलिकॉन और इंगट–वेफर जैसे चुनिंदा सेक्टरों और गतिविधियों में निवेश के प्रस्तावों पर 60 दिनों के भीतर निर्णय कर दिया जाएगा। दरअसल 2020 में लद्दाख के गलवान संघर्ष के बाद भारत ने चीन सहित पड़ोसी देशों से आने वाले निवेश पर कड़ी निगरानी और सख्त मंजूरी की शर्तें लागू कर दी थी। उस समय सरकार का मकसद था कि भारत की कंपनियों पर किसी तरह का विदेशी नियंत्रण ना हो सके। लेकिन अब सरकार का मानना है कि अगर निवेश नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से आता है तो इससे भारतीय उपभोग को फायदा हो सकता है। सरकार ने तय किया है कि इन देशों से कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, पॉलीसिलिकॉन और इंगट–वेफर जैसे चुनिंदा सेक्टरों और गतिविधियों में निवेश के प्रस्तावों पर 60 दिनों के भीतर निर्णय कर दिया जाएगा। सेक्टरों की लिस्ट में बाद में बदलाव भी किया जा सकता है। कहा गया कि निवेश करने वाली इकाई पर नियंत्रण और उसमें बहुमत हिस्सेदारी रेजिडेंट इंडियन सिटिजन या ऐसी रेजिडेंट इंडियन यूनिट के पास होनी चाहिए, जिस पर हर समय भारतीय नागरिक का नियंत्रण हो। इसके अलावा, 10 प्रतिशत तक के षैर–नियंत्रणकारी एलबीसी लाभकारी स्वामित्वष वाले निवेशकों को स्वतः ही मंजूरी दे दी जाएगी। आमतौर पर 49: तक के इक्विटी स्वामित्व को षैर–नियंत्रणकारीष माना जाता है, जबकि लाभकारी स्वामी किसी संस्था का स्वामी और नियंत्रक होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, पीएन3 प्रतिबंध में ढील देने का राजनीतिक निर्णय आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24 के बाद लिया गया, जिसमें भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए चीनी कंपनियों से निवेश आकर्षित करने की प्रबल वकालत की गई थी। नीति आयोग के सदस्य राजीव गाबा की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने भी विनिर्माण क्षेत्र के हित में चीनी निवेश पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की सिफारिश की थी। बेनेफिशियल ओनरशिप की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है। बेनेफिशियल ओनरशिप निवेश करने वाली इकाई के स्तर पर देखी जाएगी। जिन कंपनियों में इन देशों के निवेशकों की बेनेफिशियल ओनरशिप 10 होगी, उनके एफडीआई प्रस्ताव ऑटोमैटिक रूट से मंजूर किए जाएंगे। अभी तक किसी कंपनी में इन देशों का एक भी शेयरधारक होने पर एफडीआई के लिए भारत सरकार के शीर्ष स्तर से मंजूरी की जरूरत होती थी। हालांकि है इस छूट के बावजूद विभिन्न सेक्टरों में एफडीआई की जो सीमा तय की गई है, वह लागू होगी। भारत ने एफडीआई के मामले में 17 अप्रैल 2020 को प्रेस नोट 3 की व्यवस्था बनाई थी। इसके तहत जिन देशों से भारत की थल सीमा जुड़ती है, अगर वहां के शेयरहोल्डर किसी कंपनी में हों, तो ऐसी कंपनी को भारत के किसी भी सेक्टर में निवेश के लिए सरकार से मंजूरी लेने की बात तय की गई थी। कोविड के दौरान कंपनियों का वैल्यूएशन काफी घट जाने के बीच उनमें निवेश के जरिए उनका स्वामित्व विदेशी हाथों में न चला जाए, इसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया था। हालांकि उसी साल जून में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के रक्तरंजित संघर्ष के बाद कड़ाई और बढ़ा दी गई। सरकारी बयान में कहा गया पॉलिसी में बदलाव का उद्देश्य स्टार्टअप्स और डीप टेक्नालॉजी स्टार्टअप्स के लिए ग्लोबल फंड्स से ज्यादा एफडीआई लाना और कारोबारी सहूलियत बढ़ाना है। दरअसल भारत तेजी से मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा है। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारी निवेश की जरूरत है। ऐसे में चीन की कई बड़ी कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाने और निवेश करने की इच्छुक बताई जा रही है। तो इसलिए सरकार का मानना है कि अगर सही नियमों और सुरक्षा जांच के साथ निवेश की अनुमति दी जाए तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिल सकता है। हालांकि इस फैसले को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के साथ रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सेक्टर में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। सिर्फ उन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा जहां भारत को तकनीक और पूंजी की जरूरत है। अगर यह नीति लागू होती है तो भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आ सकता है। इससे नई फैक्ट्रियां लगेंगी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भारत वैश्विक सप्लाई चेन में और मजबूत हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत आर्थिक फायदे और रणनीति सुरक्षा के बीच संतुलन बना पाएगा? चीन के निवेश को लेकर मोदी सरकार का यह कदम आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों पर असर डाल सकता है। बहरहाल, मोदी सरकार का चीनी निवेश नियमों (पीएन3) में ढील देने का फैसला एक व्यावहारिक लेकिन चुनौतीपूर्ण कदम है। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने और रोजगार बढ़ाने के लिए विदेशी पूंजी और तकनीक की सख्त जरूरत है। लेकिन, दूसरी ओर चीन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारा मानना है कि यह फैसला सरकार की आर्थिक कूटनीति का एक बड़ा परीक्षण है। अगर शनियंत्रित निवेशश और श्सुरक्षाश के बीच यह मुश्किल संतुलन साध लिया जाता है, तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम–चेंजर साबित होगा। हालांकि, इसकी असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जमीनी स्तर पर इन सुरक्षा मानकों और शर्तों को कितनी कड़ाई और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाता है।

असम में चुनाव से ठीक पहले हिमंत के राजनीतिक आख्यान को झटका

डॉ. ज्ञान पाठक

इसके बड़े राजनीतिक नतीजे हुए, न सिर्फ एआईयूडीएफ के अंदर, बल्कि एनडीए और उनके जनाधार के अंदर भी। इनमें से दो विधायकों को एआईयूडीएफ ने एनडीए समर्थित उम्मीदवार को समर्थन देने के कारण निलंबित कर दिया। विपक्षी कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने सत्तारूढ़ भाजपा पर एक ऐसी पार्टी से मदद लेने का आरोप लगाया जिसकी उसने पहले बुराई की थी। यह एक राजनीतिक विवाद बन गया असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का राजनीतिक आख्यान अब से कुछ ही हफ्तों में अप्रैल–मई में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कमजोर हो गया है, जिसे उन्होंने बारपेटा में मौजूद फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से पूर्व राष्ट्रपति का नाम हटाकर वापस लाने की कोशिश की है। मुख्य रूप से भाषाई, जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ असमिया पहचान का उनका लंबे समय से चला आ रहा राजनीतिक आख्यान को हाल ही में तब गंभीर झटका लगा था, जब उन्होंने 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के लिए एआईयूडीएफ के तीन मुस्लिम विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया था।जब लोगों ने एआईयूडीएफ विधायकों से समर्थन मिलने पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के असली रंग की ओर इशारा करते हुए बातें करनी शुरू की, तो उन्हें अपने पहले के आख्यान के कमजोर होने की चिंता होने लगी। वह अपनी पुरानी कहानी को फिर से शुरू करना चाहते थे और उन्होंने फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का नाम बदलकर बारपेटा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कर दिया, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि वह अभी भी अपनी पुरानी कहानी पर काम रहेंगे, हालांकि उन्होंने एआईयूडीएफ के तीन विधायकों का समर्थन लिया है। फिर भी, राजनीतिक नुकसान तो पहले ही हो चुका है।कई दूसरे कारणों से भी हिमंत बिस्वा सरमा अब उतने मजबूत राजनीतिज्ञ नहीं हैं जितने वह 2021 में थे, जब वह राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। 2026 का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में पहला होगा, जिसकी परीक्षा होनी है। इस बीच, 2023 में असम के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन हुआ। 2024 का लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में हुआ, जिसमें भाजपा ने 14 में से 9 सीटें जीती थीं, और 126 में से 75 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी। उनके राजनीतिक आख्यान के कमजोर होने को तब झटका लगा जब उनकी सरकार समर्थित राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार को बदरुद्दीन अजमल की नेतृत्व में मुस्लिम–जनाधार वाली पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के विधायकों–करीम उद्दीनबरभुइया, जाकिर हुसैन लस्कर, और निजामुद्दीन चौधरी ने समर्थन देते हुए उनके नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किए।इसके बड़े राजनीतिक नतीजे हुए, न सिर्फ एआईयूडीएफ के अंदर, बल्कि एनडीए और उनके जनाधार के अंदर भी। इनमें से दो विधायकों को एआईयूडीएफ ने एनडीए समर्थित उम्मीदवार को समर्थन देने के कारण निलंबित कर दिया। विपक्षी कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने सत्तारूढ़ भाजपा पर एक ऐसी पार्टी से मदद लेने का आरोप लगाया जिसकी उसने पहले बुराई की थी। यह एक राजनीतिक विवाद बन गया क्योंकि भाजपा और एआईयूडीएफ खुलेआम एक–दूसरे की दुश्मन पार्टियां हैं, खासकर असम में आप्रवासी और पहचान की राजनीति जैसे मुद्दों पर। इसीलिए उनमें कोई भी आपसी मिलीभगत या सहयोग– भले ही अप्रत्यक्ष हो– राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो जाता है।क्षति नियंत्रण के लिए असम सरकार ने 10 मार्च को फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का नाम बदलकर बारपेटा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल करने का फैसला किया। कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दी, और मुख्यमंत्री हिमंत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बदलाव का कारण बताते हुए कहा, श्हमारे सभी मेडिकल कॉलेजों के नाम उनकी जगहों के नाम पर रखे गए हैं। हम गुवाहाटी, धुबरी, सिलचर, बोंगईगांव, विश्वनाथ और शोणितपुर के मेडिकल कॉलेजों में ऐसा देखते हैं। किसी तरह, बारपेटा वाले का नाम फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रख दिया गया था, जो दूसरे मेडिकल कॉलेजों के नाम रखने के तरीके से मेल नहीं खाता,श उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट ने विभ्रम से

बचने के लिए इस संस्थान का नाम बदलने का फैसला किया। पूर्व राष्ट्रपति का नाम हटाने के बाद उन्होंने कहा, श्क्योंकि फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे और असम से पहले राष्ट्रपति थे, इसलिए कैबिनेट ने फैसला किया कि उनके नाम पर उसी या उससे ऊंचे दर्जे का कोई दूसरे शैक्षणिक या सांस्कृतिक संस्थान का नामकरण किया जाएगा। हम उनके नाम को जिंदा रखने के लिए इस बारे में फैसला लेंगे।श लोग पूर्व राष्ट्रपति का नाम हटाने की इस घटना को पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की एक घटना के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, जहां चुनाव होने वाले हैं, और जहां भाजपा भारत के मौजूदा राष्ट्रपति का अपमान करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना कर रही है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या भाजपा ने मेडिकल कॉलेज के नाम से पूर्व राष्ट्रपति का नाम हटाकर उनका सम्मान किया है? ध्यान देने वाली बात यह है कि जब से बीजेपी केंद्र और राज्यों में सत्ता में आई है, उसकी सरकारें हिंदुत्व की राजनीति के तहत संस्थानों, शहरों, सड़कों, या यहां तक कि गलियों और गांवों के नाम बदल रही हैं।

शासन के निर्देश पर जौनपुर में थोक मेडिकल फर्मों का भौतिक सत्यापन शुरू

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के विशेष निर्देश पर जनपद में थोक मेडिकल एजेंसियों के स्थायित्व और दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन अभियान शुरू कर दिया गया है। जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने शुक्रवार से मड़ियाहूं और मछलीशहर तहसील क्षेत्रों में औचक निरीक्षण की कार्रवाई शुरू की। अभियान के पहले ही दिन की जांच में कई चौंकाने वाले

तथ्य सामने आने लगे हैं। अब तक 10 थोक मेडिकल फर्मों का औचक निरीक्षण और सत्यापन किया जा चुका है। जांच के दौरान फर्म संचालकों द्वारा आवेदन में दिए गए दुकान और गोदाम के पते का भौतिक सत्यापन किया गया, साथ ही वहां तैनात तकनीकी व्यक्ति (फार्मासिस्ट) की उपस्थिति भी जांची गई। जिला औषधि निरीक्षक ने रजत पांडेय ने बताया कि जिन दुकानों के परिसर किराये पर संचालित हो रहे हैं, उनके रजिस्टर्ड किरायानामे और अन्य वैध दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त संबंधित तहसील प्रशासन के माध्यम से भी दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि औषधि दुकानों के संचालन के लिए शासन द्वारा निर्धारित अनिवार्य मानकों के अनुपालन की भी जांच की जा रही है। इस सघन सत्यापन अभियान का मुख्य उद्देश्य कोडीन और एनआरएक्स श्रेणी की नशीली दवाओं के अवैध भंडारण तथा बिक्री पर प्रभावी रोक लगाना है। रजत कुमार पांडेय ने कहा कि शासन द्वारा जारी नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत जिले की सभी थोक दवा दुकानों का भौतिक सत्यापन युद्धस्तर पर किया जा रहा है। सत्यापन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ड्रग एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ भी संवाद स्थापित किया गया है। उन्होंने जिले के सभी मेडिकल एजेंसी संचालकों से अपील की है कि वे सत्यापन प्रक्रिया में विभाग का सहयोग करें। समय पर सत्यापन होने से व्यापार संचालन में पारदर्शिता बनी रहेगी और भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से भी बचा जा सकता है।

गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में आप का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर, 14 मार्च। यूपी के जौनपुर में देश में बढ़ती महंगाई, एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि और गैस की किल्लत के विरोध में आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जौनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। पार्टी के राष्ट्रीय नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवाह्न पर हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राम रतन

विश्वकर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर में 120 रुपये की बढ़ोतरी से गरीब और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। बढ़ती महंगाई से आम जनता की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है और छोटे व्यापारियों के सामने भी संकट खड़ा हो गया है। गैस की किल्लत से होटल, ढाबा और छोटे खाद्य व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं। जिला उपाध्यक्ष श्वेता चौधरी ने कहा कि देश में उपयोग होने वाली लगभग 60 प्रतिशत एलपीजी विदेशों से आयात की जाती है और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस समस्या से निपटने के लिए ठोस रणनीति बनाने में विफल रही है। महिला प्रकोष्ठ की जिला उपाध्यक्ष वंदना मिश्रा ने कहा कि रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का सबसे अधिक असर महिलाओं और गृहिणियों पर पड़ रहा है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए रसोई चलाना कठिन हो गया है। आप नेताओं ने ज्ञापन के माध्यम से घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतें वापस लेने, गैस पर विशेष सब्सिडी देने और महंगाई पर नियंत्रण के लिए प्रभावी नीति लागू करने की मांग की।

कोडीन कफ सिरप तस्करी के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े बहुचर्चित मामले में जौनपुर की अदालत ने आरोपी सौरभ गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो शारिक सिद्दीकी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी को अग्रिम राहत देना उचित नहीं है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि आरोपी को पहले भी इसी प्रकरण में उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत नहीं मिली थी। नगर कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज कोडीन कफ सिरप की तस्करी मामले में आरोपी सौरभ गुप्ता पुत्र शंकर लाल गुप्ता, निवासी बालवरगंज थाना सुजानगंज जौनपुर के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) तथा एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(ग), 27(क) और 29 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

करोड़ों रुपये के कोडीन कफ सिरप तस्करी रैकेट की जांच जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय और एसआईटी टीम द्वारा की जा रही थी। जांच के दौरान 12 नवंबर 2025 को अधिकारियों ने मेसर्स गुप्ता ट्रेडिंग मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की, लेकिन मौके पर दुकान बंद मिली। संबंधित मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर आरोपी के पिता शंकर लाल गुप्ता ने बताया कि प्रतिष्ठान फिलहाल बंद कर दिया गया है। जिला औषधि निरीक्षक रजत पांडेय की विस्तृत जांच और उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने माना कि आरोपी लंबे समय से लाइसेंस के दुरुपयोग के जरिए अवैध गतिविधियों में शामिल रहा है। अदालत ने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी समाज के लिए गंभीर खतरा है और ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत देने से जांच प्रक्रिया तथा गवाहों के साक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि अदालत ने यह स्पष्ट किया कि आरोपी नियमित जमानत के लिए आवेदन देने के लिए स्वतंत्र है।

'जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक संपन्न'

रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहांपुर' जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक कैम्प कार्यालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा ने जनगणना के संबंध में विस्तार से बताया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत की जनगणना–2027 सम्बन्धी प्रथम चरण अर्थात मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना पूरी तरह डिजिटल रूप में सम्पन्न करने का कार्य उत्तर प्रदेश राज्य में 22 मई, 2026 से 20 जून, 2026 तक की अवधि के दौरान किये जाने का निर्णय लिया गया है एवं इस बार जनगणना में कार्य आरम्भ होने से ठीक 15 दिन पहले स्वगणना के लिए विकल्प भी प्राविधानित है। उन्होंने जनगणना–2027 से सम्बन्धित कार्य यथा पोर्टल के माध्यम से मकानसूचीकरण, ब्लॉक का गठन, स्लम ब्लॉक का गठन, पदाधिकारियों (प्रगणक एवं सुपरवाईजर) की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण कार्य को ससमय गुणवत्तापरक रूप से सम्पन्न कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनगणना के लिए ब्लॉक काटने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है इसमें सावधानी बरती जाए। जनगणना हेतु चार्ज ऑफिसर, फील्ड ट्रेनर्स प्रथम एवं द्वितीय, सुपरवाइजर प्रगणक (इन्यूमेरेटर) को प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण में जनगणना कार्य से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जनगणना की प्रक्रिया, परिभाषाएं, हाउस लिस्टिंग, लेआउट मैप तथा आंकड़ा संकलन की विधियों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की जाए। जनगणना देश का अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से जनसंख्या से संबंधित सटीक आंकड़े प्राप्त होते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाता है, इसलिए जनगणना कार्य को पूरी गंभीरता, पारदर्शिता एवं सावधानी के साथ संपन्न कराना आवश्यक है। जनगणना 2027 के अंतर्गत हाउस लिस्टिंग एवं हाउस नंबरिंग की प्रक्रिया, परिवार विवरण अंकन, भवनों के चिन्हांकन तथा लेआउट मैप तैयार करने की विधि का विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही प्रशिक्षणार्थियों को प्रपत्रों को सही तरीके से भरने, सूचनाओं का सत्यापन करने आदि के संबंध में भी जानकारी दी जाए। प्रगणक को एमएलबी एप इंस्टॉल कर कार्य करना है। नजरी नक्शे से भवनों एवं जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या भरनी है। घर–घर जाकर मोबाइल एप में सूचना दर्ज करनी है। डेटा को नियमित रूप से सिंक करना है। यदि किसी परिवार ने स्वगणना की है तो एसई आईडी प्राप्त कर डेटो सत्यापित करते हुए स्वीकार करना है या आवश्यकतानुसार एडिट करना है। पर्यवेक्षक(सुपरवाइजर) को क्षेत्र में सभी एचएलबी सीमाओं का सत्यापन करना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि कोई एचएलबी छूट न जाए अथवा उसका दोहराव न हो। पर्यवेक्षक प्रत्येक प्रगणक की प्रगति की निगरानी भी करेंगे। जनगणना से संबंधित कार्य समयबद्ध एवं त्रुटिरहित ढंग से पूर्ण किया जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ अपराजिता सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे।

स्टेट बैंक पेशनर हमारे अभिन्न अंग एवं उनका योगदान अमूल्य –अनिल कुमार, महाप्रबंधक

लखनऊ (आर एल पाण्डेय). "स्टेट बैंक सदैव अपने पेंशनर्स को बाधारहित पेंशन भुगतान के अलावा चिकित्सा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु निरंतर प्रयासरत रहने के अलावा उनके हितों के प्रति पूर्णतः संवेदनशील व कटिबद्ध है क्योंकि वे हमारे अभिन्न अंग हैं और उनका योगदान हमारे लिए अमूल्य है" यह विचार शुक्रवार को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आयोजित स्टेट बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय, लखनऊ के महाप्रबंधक अनिल कुमार ने व्यक्त किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी वरिष्ठ साथियों का सम्मान एवं उन्हें बेहतरीन सुविधाएं देना हमारा परम कर्तव्य भी है। आज के सेवानिवृत्त व्यक्ति बीते कल की अक्षयनिधि है एवं उनके द्वारा किए गए सेवाकालीन कार्य हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस बैठक का उद्देश्य आपसी मेलजोल के अलावा अपने अधिकारों, सम्मान और सुविधाओं की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। बैंक ने विगत वर्ष पेंशनभोगियों के लिए कई नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है जिनका लाभ सभी पेंशनभोगियों व उनके परिवार को मिलेगा। वर्तमान में लखनऊ मंडल में लगभग 19000 सेवानिवृत्त पेंशनर हैं। इस कार्यक्रम में प्रशासनिक कार्यालय, लखनऊ (पश्चिम) के उप महाप्रबंधक धीरज कुमार ने कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारी भी हमारे परिवार के सदस्य हैं और बैंक अपने परिवार के सभी सदस्यों का आजीवन अच्छी तरह से ख्याल रखता है। विगत वर्ष हमने अपने सेवानिवृत्त साथियों के लिए 5 स्वास्थ्य शिविर एवं चर्चा कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें पेंशनभोगियों की समस्याओं का निराकरण किया गया। आगे भी यह क्रम अनवरत जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि "सेवानिवृत्ति विश्राम नहीं, बल्कि अनुभव से समाज को दिशा देने का अवसर है।" इस कार्यक्रम में स्थानीय प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक राजीव कुमार, कौशलेन्द्र कुमार, उप महाप्रबंधक एवं सीडीओ धीरेन्द्र महेश व बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा एसबीआई पेंशनर्स एसोसिएशन, लखनऊ मंडल के अध्यक्ष दिनेश चन्द्र, महासचिव अतुल स्वरूप एवं पेंशनर्स फेडरेशन के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का समन्वयन मुख्य प्रबंधक (मानव संसाधन) आशुतोष शुक्ल ने किया।

साइकॉन 2026 में तकनीक और मानव मन के रिश्ते पर चर्चा

लखनऊ (आर एल पाण्डेय)। टाइम क्या हुआ? सुबह उठते ही इस सवाल का जवाब आप अपने फोन से पूछते हैं। कॉलेज डेज में क्लास ज्वाइन करने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं। यहीं से आप मोबाइल की गिरफ्त में आते हैं। ऐसे ही डिजिटल डोपामिन से जुड़े विभिन्न विषयों पर दो दिवसीय 'साइकॉन 2026' राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान चर्चा की गई कि तकनीक तेजी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रही है और इसका असर हमारे सोचने–समझने, भावनाओं, व्यवहार और फैसले लेने क्षमताओं तक में दिखाई देने लगा है। निर्वाण हॉस्पिटल द्वारा आयोजित सम्मेलन में देश भर के मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, शोधकर्ता और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य सलाहकार, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश श्री अवनीश अवस्थी उपस्थित रहे। इसके अलावा निर्वाण हॉस्पिटल के संस्थापक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. एच. के. अग्रवाल, डॉ. दीप्तांशु अग्रवाल, मेडिकल डायरेक्टर, निर्वाण हॉस्पिटल, डॉ. टी.बी. सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, आईएचबीएएस, दिल्ली, डॉ. प्रांजल अग्रवाल, डायरेक्टर, निर्वाण हॉस्पिटल, श्रीमती अस्था शर्मा, विभागाध्यक्ष – क्लिनिकल साइकोलॉजी, निर्वाण हॉस्पिटल और संगठन सचिव – साइकॉन 2026 श्री हिमांशु सिंह, डायरेक्टर, कम्पोजिट रीजनल सेंटर (सीआरसी), लखनऊ भी शामिल रहे। सम्मेलन की थीम 'माइंड इन द मशीन टेक्नोलॉजी और मानव जीवविज्ञान का संबंध' रखी गई। इस थीम के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया कि तकनीक किस तरह मानव मस्तिष्क, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित कर रही है। कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने बताया कि लाइक्स और शेयर के फेर में आकर लोग अपना मानसिक सुकून खो रहे हैं। यहां तक कि प्रेग्नेंट महिलाओं में अधिक फोन का इस्तेमाल उनके होने वाले बच्चे पर बुरा असर डाल रहा है। वहीं छोटे बच्चों में अधिक स्क्रीन टाइम मोटापे से लेकर ड्रग अब्यूज, अनिद्रा और सोचने की क्षमता को प्रभावित कर रहा है। सम्मेलन के पहले दिन हमेशा ऑनलाइन रहने के नुकसान, यौन आक्रामकता की शुरुआत, कहानियों का मनोविज्ञान, ऑनलाइन के अधिक इस्तेमाल से लेखन पर प्रभाव, आज की सुस्त लाइफस्टाइल और डिजिटल दुनिया से इंसानी शरीर में बदलाव, उम्र के साथ बदलती तकनीक और उसके असर जैसे पर चर्चा की गई। निर्वाण हॉस्पिटल के संस्थापक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. एच. के. अग्रवाल ने कहा कि तकनीक आज मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा दे रही है। हमारा उद्देश्य है कि विशेषज्ञ एक मंच पर आकर इस बदलाव को समझें और ऐसे समाधान खोजें जो मरीजों के लिए सुरक्षित और प्रभावी हों। सम्मेलन के मुख्य अतिथि एवं मुख्य सलाहकार, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश श्री अवनीश अवस्थी (से.नि. आईएएस) ने कहा कि मेंटल हेल्थ का एरिया देश में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सेंसेटिव है, जिसपर ध्यान दिया जाना चाहिए। कोरोना के दौरान बड़ी संख्या में लोग घर पर बंद थे। इस दौरान घर पर वर्किंग प्रोफेशनल्स, महिलाएं और स्टूडेंट बैठे थे और मानसिक तनाव से जूझ रहे थे। ऐसे में सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर उनकी मदद की। अगर हम क्लिनिकल सायकलॉजी और मेंटल हेल्थ के एरिया में एआई को जोड़ सकें तो इसके परिणाम अभूतपूर्व हो सकते हैं। इसके साथ ही क्लिनिकल सायकलॉजी की मदद से ड्रग एब्यूज और रिहैबिलिटेशन जैसे विषयों पर समाधान खोजने की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि स्टूडेंट्स में सिर्फ लड़के ही नहीं लड़कियां भी इसकी गिरफ्त में है। प्रो. (डॉ.) तेज बहादुर सिंह पूर्व प्रोफेसर, क्लिनिकल साइकोलॉजी ने कहा कि आज क्लिनिकल साइकोलॉजी एक ऐसे दौर में खड़ी है जहाँ मानवीय समझ और तेजी से बदलती तकनीक साथ–साथ आगे बढ़ रही हैं। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की जिम्मेदारी केवल उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि बदलती दुनिया की नई चुनौतियों को समझना भी उतना ही जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीकों का उपयोग मानसिक रोगों की शुरुआती पहचान, बेहतर आकलन और व्यक्ति–केंद्रित उपचार में नई संभावनाएँ खोल रहा है। लेकिन तकनीक के साथ संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण हमेशा केंद्र में रहना चाहिए।

जौनपुर में एसआई भर्ती परीक्षा शुरू, 19 केंद्रों पर कड़ी निगरानी के बीच हो रही परीक्षा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में उप निरीक्षक (एसआई) पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2025 की लिखित परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई। परीक्षा 14 और 15 मार्च को जिले के 19 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की जा रही है। परीक्षा दो दिनों तक चार पालियों में संपन्न होगी। प्रत्येक दिन दो पालियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। प्रत्येक पाली में 7,920 अभ्यर्थी परीक्षा में

शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। जिले में 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 19 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 19 केंद्र व्यवस्थापक तथा लगभग 700 कक्ष निरीक्षकों की तैनाती की गई है। नगर के टीडी कॉलेज सहित सभी परीक्षा केंद्रों पर सुबह 8 बजे से ही अभ्यर्थियों की सघन जांच की जा रही है। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों के जूते, मोजे, शर्ट के कॉलर और बाहों की जांच की जा रही है। साथ ही घड़ी, रुद्राक्ष माला सहित अन्य वस्तुएं उतरवाकर ही प्रवेश दिया जा रहा है। महिला अभ्यर्थियों के आभूषणों, यहां तक कि चूड़ियों तक की भी जांच की जा रही है, ताकि किसी प्रकार की नकल की संभावना न रहे। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया जाए। उन्होंने सभी केंद्र व्यवस्थापकों, सेक्टर मजिस्ट्रेटों और स्टैटिक मजिस्ट्रेटों को सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सघन तलाशी ली जाए, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाए, पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए तथा यातायात व्यवस्था सुचारू रखी जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बी आर पी इंटर कॉलेज चेक करने पहुंचे डीएम डॉ. दिनेश चंद्र ने बताया कि परीक्षा को सकुशल और सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार परीक्षा को निष्पक्ष और नकलविहीन बनाने के लिए सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है और सभी अधिकारी पूरी सतर्कता के साथ निगरानी कर रहे हैं।

छात्रों का शैक्षणिक भ्रमणरूशैक्षिक भ्रमण बच्चों के व्यवहारिक ज्ञान वृद्धि में सहायक –प्रशांत मिश्र

जौनपुर/शाहगंज ब्लाक स्थित कम्पोजिट विद्यालय पकड़ी के छात्रों का दल शुक्रवार को प्रातः वाराणसी के लिए प्रधानाध्यापक हरिशंकर पाल के नेतृत्व में शैक्षणिक भ्रमण हेतु रवाना हुआ। रावनगी के समय अभिभावकों एवं छात्रों में उत्साह देखा गया। बच्चे सारनाथ स्थित महात्मा बुद्ध के धर्म

चक्र प्रवर्तन स्थल को देख कर उत्साहित रहे, तत्पश्चात नमो घाट एवं रामनगर का किले पर भी गए। बच्चे निरंतर अपने जिज्ञासा के अनुसार अध्यापकों से प्रश्न कर रहे थे। संवाददाताओं से बातचीतके क्रम में प्रशांत मिश्र जिला उपाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ ने बताया कि जनपद में ऊर्जावान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल एवं ब्लॉक शाहगंज में कर्मठ खंड शिक्षा अधिकारी बसंत शुक्ला के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में बच्चों का शैक्षिक भ्रमण कराया जा रहा है जो बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण मिस सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने बताया की कंपोजिट विद्यालय पकड़ी के 38 बच्चों का दल भ्रमण हेतु रवाना हुआ और सकुशल भ्रमण संपन्न हुआ रवानगी के समय ग्राम प्रधान थानेदार यादव सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। अखिलेश कुमार, धीरेन्द्र कुमार, अभिलाषा यादव, जय प्रकाश यादव, अरशद कमाल, तजीम फात्मा सहित विद्यालय के सभी शिक्षक निरन्तर अपना योगदान देते रहे।

डंपर ने एसयूवी को मारी टक्कर, एक की मौत और चार लोग घायल

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी के श्रावस्ती में शुक्रवार की सुबह डंपर ने एसयूवी को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जबकि, चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी समय भिनगा आ रहे एसएसबी के उप कमांडेंट ने घायलों को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे का कारण घना कोहरा बताया जा रहा है। हादसा चिल्हारिया–भिनगा मार्ग पर टेपरा के पास हुआ। बताया गया कि सिरसिया बाजार निवासी मनीष कुमार सोनी (33) के घर मांगलिक कार्यक्रम है। सुबह वह सब्जी खरीदने के लिए एसयूवी से मंडी जा रहे थे। उनके साथ उनके रिश्तेदार सिद्धार्थनगर निवासी संतोष कुमार सोनी (31), सूर्यभान सोनी (32), ओजेश (18) व अतुल सोनी (17) भी थे। टेपरा के पास एसयूवी में डंपर ने टक्कर मार दी। इस दौरान एस्कॉर्ट के साथ रनियापुर सीमा चौकी से भिनगा जा रहे एसएसबी के उप कमांडेंट गोवर्धन पुजारी ने हादसा देख अपना काफिला रोक दिया। उन्होंने तत्काल पुलिस व एंबुलेंस को इसकी सूचना दी। घायलों को वाहन से बाहर निकलवाया। इसके बाद उन्हें जिला चिकित्सालय, भिनगा में भर्ती कराया गया। वहां चिकित्सकों ने संतोष की मौत होने की पुष्टि की। कमांडेंट अमरेंद्र कुमार वरुण के निर्देश पर एसएसबी की क्यूआरटी टीम जिला अस्पताल भी पहुंचीं।

गैस एजेंसियों का एसडीएम सोहावल ने किया निरीक्षण

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।सोहावल तहसील क्षेत्र में घरेलू गैस को लेकर गैस एजेंसियों पर लगी लंबी कतारों की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे के निर्देश पर उप जिलाधिकारी सविता देवी ने सप्लाई इंस्पेक्टर पूजा सिंह व रौनाही थाना प्रभारी के साथ इंडियन गैस एजेंसी व एचपी गैस एजेंसी का निरीक्षण किया।इस दौरान स्टॉक रजिस्टर और गैस गोदाम की जांच की गई। उपभोक्ताओं ने बुकिंग के बाद भी गैस न मिलने की शिकायत की, जिस पर एसडीएम ने एजेंसी संचालक को निर्देश दिया कि जिन उपभोक्ताओं की गैस पहले से बुक है उन्हें होम डिलीवरी के माध्यम से गैस उपलब्ध कराई जाए। साथ ही चेतावनी दी कि ढाबा या होटल पर घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।इस संबंध मे एसडीएम ने कहा कि गैस की कोई कमी नहीं है और लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। अब देखना यह है कि क्या अगले दिन क्या होम डिलीवरी होगी, या एजेंसी एक बार फिर भीड़ की गवाह बनेगी।

राष्ट्रपति मुर्मू के आगमन पर 19 मार्च को राम मंदिर मे वीआईपी व सुगम दर्शन पास रहेंगे निरस्त

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।रामनवमी मेले में राष्ट्रपति मुर्मू 19 मार्च को राम मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने आ रही हैं। सुरक्षा की दृष्टि को लेकर 19 मार्च को वीआईपी दर्शन पास व सुगम पा नहीं मिलेंगे।वही पहले से बने सुगम व विशिष्ट दर्शन पास भी निरस्त रहेंगे। इस संबंध में ट्रस्ट के पदाधिकारी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि चौत्र नवरात्र की वर्ष प्रतिपदा से शुरू होने वाले रामनवमी मेले के पहले ही दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अयोध्या आगमन को लेकर विशेष व्यवस्था की जा रही है।इस दिन राम मंदिर में वीआईपी दर्शन व सुगम पास जारी नहीं किए जाएंगे।श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी डॉक्टर मिश्रा के अनुसार 19 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक दो–दो घंटे के स्लॉट में जारी किए जाने वाले सुगम और विशिष्ट दर्शन पास पूरी तरह बंद रहेंगे।ट्रस्ट के पदाधिकारी डॉ. मिश्र ने बताया कि इस तिथि के लिए ऑनलाइन बनाए जा चुके सभी पास भी निरस्त माने जाएंगे।श्रद्धालुओं को इस दिन सामान्य व्यवस्था के तहत ही दर्शन की सुविधा मिलेगी।मंदिर प्रशासन के अनुसार मंगला आरती, शृंगार आरती और शयन आरती के पास को लेकर अभी विचार–विमर्श चल रहा है।भीड़ की स्थिति और जिला प्रशासन की सहमति के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

दो दिवसीय पुलिस सब–इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पहले दिन सकुशल संपन्न

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।शनिवार को अयोध्या में दो दिवसीय पुलिस सब–इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पहले दिन सकुशल संपन्न हुई। पहले दिन कुल 12 परीक्षा केंद्रों पर कुल 5755 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए।जबकि 2405 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे।मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को प्रथम पाली में 4080 अभ्यर्थियों में से कुल 2849 अभ्यर्थी तथा 1231 अभ्यर्थी अनुपस्थित

रहे।जबकि द्वितीय पाली में 4080 अभ्यर्थियों में से 2906 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल रहे और 1174 अभ्यर्थी परीक्षा मे अनुपस्थित रहे।परीक्षा को निष्पक्ष व पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के साथ खुद परीक्षा केदो का निरीक्षण करते हुए दिखाई दिए इसके अलावा एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के साथ परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया।परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल विहीन कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई।प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी ड्यूटी में लगाए गए।परीक्षा के दौरान अफवाह व और नकल रोकने के लिए सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी गई।डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि सभी केंद्रों पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए है।प्रश्नपत्रों के सुरक्षित आवागमन के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगाए गए।परीक्षा की निगरानी के लिए उड़ाका दल का गठन किया गया ताकि नकल पर रोक लग सके। वही प्रथम हुआ द्वितीय पाली में परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों ने कहा कि पेपर आसान था और उन्हें सफलता की उम्मीद है।

वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भव्य शोभायात्रा व देवाराधन पूर्वक श्रीमद्भागवत कथा का हुआ शुभारंभ

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।जिले के पूराबाजार क्षेत्र के राजेपुर में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण,भव्य शोभायात्रा और देवआराधन के साथ श्रद्धा एवं भक्ति के वातावरण में हुआ। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल देखने को मिला।कथा के द्वितीय सत्र में प्रवचन करते हुए आचार्य ज्ञान चंद्र द्विवेदी ने कहा कि पुराण भारतीय जीवन साहित्य के अमूल्य रत्न हैं और अतीत को वर्तमान से जोड़ने वाली स्वर्णमयी श्रृंखला के समान हैं। उन्होंने कहा कि भगवान की कथा मनुष्य के हृदय में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का संचार करती है।आचार्य द्विवेदी ने कहा कि भगवान की कथा स्वयं भगवान से भी अधिक उदार मानी गई है, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से पापी से पापी व्यक्ति भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि धुंधुकारी जैसा उग्र पापी भी भगवत्कथा के प्रभाव से भगवान के धाम का अधिकारी बन गया। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं और कृष्ण का अर्थ ही परम आनंद है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति आनंद की खोज में लगा हुआ है, लेकिन वास्तविक आनंद किस प्रकार प्राप्त किया जाए, यह अधिकांश लोग नहीं जानते। भौतिकतावादी दृष्टिकोण से जीवन जीने पर मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के प्रयास में निराशा का सामना करता है। आचार्य ने कहा कि दिव्य आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने जीवन दर्शन को समझना होगा और उसे समझने का सबसे सरल माध्यम भगवान की कथा है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही अंतरंग भाव हैं, जो अंतरूकरण में निवास करने वाले परमात्मा का साक्षात स्पर्श कराते हैं। शास्त्रों के अनुसार इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से भी परे परमात्मा का स्थान है। उन्होंने बताया कि श्रीमद्भागवत के महात्म्य में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवत्कथा मनुष्य के हृदय में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को पुष्ट करती है। भगवान, भगवान की कथा और भक्तों की शरणागति कभी निष्फल नहीं होती। कथा में मुख्य यजमान भगवान भक्श सिंह, आशा सिंह तथा गोसाईगंज विधायक अभय सिंह सहित क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे।कथा के दौरान पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत रहा।

पुलिस की वर्दी मे ठगी करने वाले आरोपियों को अभी तक नहीं गिरफ्तार कर सकी पुलिस

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्य।जिले में पुलिस की वर्दी पहनकर ठगी करने वाले बदमाश काफी रूप से सक्रिय हो गए है।इस प्रकार की घटनाये थाना कुमारगंज व थाना रौनाही क्षेत्र में हो चुकी है परंतु संबंधित थाने की पुलिस इसका खुलासा अभी तक नहीं कर सकी है। अभी तक पुलिस हवा में ही सिर्फ तीर चला रही है और इससे संबंधित आरोपी पुलिस की पकड़ से काफी दूर हैं।जिसके चलते एक तरफ जहां पुलिस की वर्दी में ठगी करने वाले बदमाशों को लेकर भय वहीं दूसरी तरफ इस मामले में पुलिस के प्रति आक्रोश भी स्थानीय लोगों में दिखाई दे रहा है।बताते चले कि थाना कुमारगंज क्षेत्र में सरसों बेचने के नाम पर व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है।हाल ही में कुमारगंज थाना क्षेत्र में एक व्यापारी से 50 हजार रुपये ठग लिए गए, जबकि इससे पहले रौनाही थाना गेट पर भी इसी तरह की वारदात हो चुकी है।दोनों मामलों में पुलिस अभी तक आरोपित को गिरफ्तार नहीं कर सकी है।कुमारगंज के बवां रोड निवासी व्यापारी अनिरुद्ध की दुकान पर करीब 15 दिन पहले शाम के समय पुलिस की वर्दी पहने एक व्यक्ति बाइक से पहुंचा। उसने खुद को थाने का दीवान बताते हुए कहा कि थाना प्रभारी के कहने पर वह सरसों का भाव लेने आया है। उसने बताया कि थाने में नौ क्विंटल सरसों रखी है जिसे बेचना है। बातचीत के बाद 70 रुपये प्रति किलो से मोलभाव करते हुए 63 रुपये प्रति किलो पर सौदा तय हुआ।सौदा तय होने के बाद आरोपित ने व्यापारी से 50 हजार रुपये अग्रिम ले लिए और सरसों लादने के लिए साथ चलने को कहा।व्यापारी भरोसा करके उसके साथ ई–रिक्शा से थाने पहुंच गया।थाना गेट पर पहुंचने के बाद ठग ने कमरे की चाबी गिर जाने का बहाना बनाकर उसे खोजने की बात कही और वहां से फरार हो गया।काफी देर इंतजार करने के बाद व्यापारी ने थाना प्रभारी संतोष कुमार से जानकारी ली, तब ठगी का पता चला।पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।इसी तरह 7 फरवरी को रौनाही थाना गेट पर भी फर्जी पुलिसकर्मी ने सरसों बेचने के नाम पर व्यापारी राधेश्याम वर्मा से 40 हजार रुपये ठग लिए थे।सीओ मिल्कीपुर अजय कुमार सिंह ने बताया कि दोनों मामलों की जांच चल रही है और जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा।।

जिला जज ने किया लोक अदालत का किया शुभारंभ

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। शनिवार को को मॉ सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलन के साथ वृहद राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ जिला जज रणंजय कुमार वर्मा ने किया।उन्होंने मॉ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलन कर किया।इस अवसर पर जिला जज न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा ने कहा कि लोक अदालत की मूल भावना में लोक कल्याण की भावना समाहित है। सुलह समझौता के दौरान सभी का मान, सभी का सम्मान, सभी को न्याय मिले इसका ध्यान रखा जाता है।राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर आपसी सुलह–समझौते के माध्यम से वादों को निस्तारित कराया जाता है।लोक कल्याण के भावना से ओत–प्रोत उसी स्वरूप को उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा विस्तार रूप देते हुए एक स्थल, एक मंच पर बहुत सारे वादों को सुलह–समझौता के आधार पर समाप्त कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित कराने के निर्देश दिये जाते हैं,।जिसमें दोनों पक्षों के हित के साथ सामाजिक प्रेम भावना भी समाहित है।कहा कि लोग मिल–जुल कर प्रेम भावना से रहे, जो समाज एवं राष्ट्र के हित में है। यदि आपसी मतभेद पनपते भी हैं, तो उसे शांत एवं सद्भाव के साथ समाप्त करने का प्रथम प्रयास दोनों पक्षों द्वारा किया जाना चाहिए।यदि प्रथम प्रयास में दोनों पक्ष सफल नहीं होते है तभी उन्हें न्यायालय के शरण जाना चाहिए। माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि जनपद न्यायालय परिसर के अतिरिक्त क्लेक्ट्रेट एवं सभी तहसीलों में आपसी सुलह–समझौता के आधार पर वादों का निस्तारण कराया जाय।इस अवसर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रंजिनी शुक्ला ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालय व कार्यालय की प्रक्रियात्मक जटिलता से इतर सस्ता, सुलभ व त्वरित न्याय सभी को उपलब्ध कराना है तथा वैकल्पिक विवाद समाधान य।सजमतदंजपअम क्पेचनजम त्मेवसनजपवदद्ध को और अधिक सुदृढ़ व प्रभावी बनाना है। यह तथ्य हम सभी से छिपा नहीं है कि मुकदमों की बढ़ती संख्या व उनके अग्रिम निस्तारण हेतु हमें एक वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता है। इस क्रम में नियमित अंतराल पर होने वाली लोक अदालत का आयोजन इसी दिशा में बढ़ाया गया एक सराहनीय कदम है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा अपने उद्बोधन में यह भी कहा गया कि सुलह समझौते के माध्यम से वादकारी के धन व समय की बचत होती है। लोक अदालत के आयोजन में आने वाले दोनों पक्षों के बैठने, शुद्ध पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था करायी गई है। लोक अदालत में आने वाले सभी व्यक्ति के सुविधा का ख्याल रखा गया है और यह प्रयास किया जा रहा है कि आज इस वृहद लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को आपसी सुलह–समझौता के माध्यम से समाप्त कराकर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्देश्य का लाभ दिलाया जा सके।बताया कि धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.ऐक्ट), बैंक वसूली वाद, श्रम विवाद वाद, विद्युत एवं जलवाद बिल, (अशमनीय वादों को छोड़कर) अन्य आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक एंव अन्य व्यवहार वाद, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सर्विस मैटर से संबन्धित वेतन, भत्ता और सेवानिवृत्ति लाभ के मामले, राजस्व वाद, जो जनपद न्यायालय में लम्बित हों, अन्य सिविल वाद आदि निस्तारित किये गये।दीपक यादव,अपर जिला जजध्नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत एवं रंजिनी शुक्ला सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ने बताया कि शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 81803 वादों को निस्तारित किया गया एवं कुल समझौता राशि मु0 182350335 रू0 है।जिसमें पीठासीन अधिकारी (वर्चुअल कोर्ट) निवेदिता सिंह ने अथक प्रयास करते हुए 32436 वादों का निस्तारण किया। उनके द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन में अत्यंत सराहनीय कार्य किया गया।रवि कांत न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा ड।ब्ज् में कुल 138 केस निस्तारण हेतु नियत थे, जिसमें से कुल 115 वाद निस्तारित किये गये, जिस पर कुल 10,14,69,769ध– रू0 की धनराशि क्षतिपूर्ति निधारित की गयी।बैंक रिकवरी से संबन्धित 1084 प्री–लिटिगेशन वाद निस्तारित किये गये तथा बैंक संबन्धित ऋण मु0– 6,88,91,512ध– रू0 का सेटेलमेंट किया गया, जो विगत लोक अदालत की तुलना में अधिक है। यह एल0डी0एम0 गणेश सिंह यादव द्वारा उठाया गया सराहनीय कदम पारिवारिक विवाद से सम्बन्धित 69 मुकदमों को निस्तारित किया गया है,जिसमें कई पुराने वाद निस्तारित किये गये।वाणिज्यिक न्यायालय से सम्बन्धित 11 मुकदमों को निस्तारित किया गया जिसमें 53,92,833ध– रू0 सेटेलमेंट किया गया।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 4256 वाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम द्वारा 2082 वादों का निस्तारण किया गया जो विगत लोक अदालत की तुलना में अधिक वाद निस्तारित किया गया है।राजस्व मामलों से संबन्धित 29608 वाद विभिन्न राजस्व न्यायालय द्वारा निस्तारित किया गया। इस मौके पर रवि कान्त पीठासीन अधिकारी एम0ए0सी0टी0, वेद प्रकाश वर्मा, पीठासीन अधिकारी, कामर्शियल न्यायालय, शिवानी जायसवाल,सुरेन्द्र मोहन सहाय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम, राकेश कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशधविशेष न्यायाधीश एस0सी0ध्एस0टी0 एक्ट, निरूपमा विक्रम, अपर जिला जजध विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट–प्रथम, रजत वर्मा, विशेष न्यायाधीश, विशेष कोर्ट सं0–01, नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत दीपक यादव अपर जनपद न्यायाधीश, अपर जनपद न्यायाधीश मोहिन्दर कुमार, प्रतिभा नारायण, प्रेम प्रकाश, इन्द्रजीत सिंह, अनिल कुमार वर्मा, अर्चना तिवारी, प्रदीप कुमार सिंह, रवि कुमार गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधांशु शेखर उपाध्याय व अन्य न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।

अमर शहीद जगदंबा पाडेय चौराहा के नाम से जाना जाएगा देवकाली बाईपास - महापौर

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा है कि देश की एकता और अखंडता अमर शहीदों की देन है। शहीदों के सम्मान में हर किसी को सदैव तत्पर रहना चाहिए।नगर निगम अयोध्या सैनिकों के सम्मान के लिए तत्पर है।उन्हें गृह एवं जल कर से राहत दिलाने के लिए नगर निगम प्रयासरत है।वह कारगिल बलिदानी जगदंबा प्रसाद पांडेय की याद में बलिदान दिवस पर देवकाली बाईपास चौराहे के नामकरण के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे।उन्होंने शिलापट्ट का अनावरण कर चौराहे का लोकार्पण किया।कार्यक्रम का संचालन भाजपा नमामि गंगे के जिला अध्यक्ष बृजेश त्रिपाठी ने किया।कार्यक्रम का आयोजन अमर शहीद के सुपुत्र विजय पांडे सूरज ने किया। इस मौके पर वीर नारी शीला पांडेय, भाजपा नेता गोकरन द्विवेदी, मंडल अध्यक्ष हेमंत जायसवाल, आलोक द्विवेदी, सुनील शास्त्री, पार्षद राजकरण, पार्षद प्रतिनिधि मंसूर अहमद, पूर्व पार्षद मनोज श्रीवास्तव, सुनीता उपाध्याय, पूर्व प्रधान जगदीश चतुर्वेदी, सुबोध चतुर्वेदी, डॉ. रंजीत सिंह, प्रेमप्रकाश मिश्र, रामसजीवन पांडेय, सुधाकर त्रिपाठी, विजय कुमार सिंह, संत विपिन दास, विवेक श्रीवास्तव, पंकज पाठक, प्रीति पांडेय, ज्योति पांडेय, मनोज तिवारी, अंजनी, शिवम पांडेय, राकेश पांडेय, रिशु, आनंद दुबे, रॉकी द्विवेदी, अनिल द्विवेदी, आशीष पांडेय, दुर्गा प्रसाद तिवारी, सच्चिदानंद मिश्र, अजय पांडेय, रामसुमेर पांडेय, उदय नारायण दुबे, रत्नेश दुबे, देवीचरण दुबे, राजबहादुर पांडेय, अनिल द्विवेदी, अजय पांडे, डीआर दुबे आदि की उपस्थिति रही। इस मौके पर अमर शहीद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और सामाजिक सरोकार से अमर शहीद की मूर्ति स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया।

मनुष्य जीवन अमूल्य, सत्संग में लगाएं मन : माता कृष्णा

भदोही, (संवाददाता)। काली देवी मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में बुधवार की शाम कथा वाचिका माता कृष्णा ने भक्तों को मनुष्य जन्म के मूल्यों को समझाया। कहा कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य है, इसलिए इस जीवन को व्यर्थ न गंवाकर भगवान की भक्ति, सत्संग और अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। बताया कि संसार में अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, लेकिन उनमें सबसे श्रेष्ठ कार्य भगवान के नाम का स्मरण, संतों का संग और मानव सेवा है।बताया कि जब मनुष्य संतों के सानिध्य में रहता है तो उसके जीवन के अनेक भ्रम दूर हो जाते हैं और उसे सही मार्ग की प्राप्ति होती है। सत्संग के माध्यम से व्यक्ति के भीतर प्रेम, दया, विनम्रता और सेवा की भावना जागृत होती है। बताया कि अहंकार, क्रोध और बुरे विचार मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं, जबकि भक्ति और सत्संग जीवन को उज्ज्वल बनाते हैं। कहा कि भगवान का नाम लेने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान नाम की महिमा इतनी बड़ी है कि जब कोई भी भगवान नाम का स्मरण करता है तो वह बड़े–बड़े भवसागर पार कर जाता है। इस मौके पर विनय उमरवैश्य, ओम सिंह, उमेश चंद विश्वकर्मा, नारायण मोदनवाल, गणेश उमरवैश्य, अंजलि मौर्या, विनीत बरनवाल आदि रहे।

हिंदी में सबसे ज्यादा और कृषि में कम परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित

भदोही, (संवाददाता)। यूपी बोर्ड परीक्षा बृहस्पतिवार को समाप्त हो गई। बृहस्पतिवार को हाईस्कूल की कृषि और इंटर की कंप्यूटर विषय की परीक्षा रही। इस बार सबसे ज्यादा हिंदी और सबसे कम कृषि में परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। पहली बार परीक्षा में एक भी परीक्षार्थी अनुचित साधन के साथ नहीं पकड़ा गया है। जिले में बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 94 केंद्र बनाए गए थे। बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से शुरू हुई। पहले दिन हिंदी की परीक्षा आयोजित की गई। बृहस्पतिवार को अंतिम दिन हाईस्कूल कृषि में पंजीकृत 75 में दो और इंटरमीडिएट के कंप्यूटर में पंजीकृत 140 में छह अनुपस्थित रहे। यूपी बोर्ड परीक्षा कराने के लिए जिले को तीन जोन और 12 सेक्टरों में बांटा गया था। इसके लिए तीनों एसडीएम को जोनल और 12 जिलास्तरीय अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया था। 94 केंद्रों पर चलने वाली परीक्षा पर नजर रखने के लिए 1734 कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में 55 हजार 688 परीक्षार्थी पंजीकृत रहे। इसके अलावा 94 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 94 अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापकों की तैनाती भी की गई थी। परीक्षा पर नजर रखने के लिए कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बना था। इसके अलावा डीआईओएस, बेसिक शिक्षा अधिकारी, लेखाधिकारी, डायट प्राचार्य, डायट प्रवक्ता समेत कुल छह सचल दस्ते बनाए गए थे।

अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराई बाइक, युवक की मौत

भदोही, (संवाददाता)। लठिया गांव के पास बृहस्पतिवार को एक बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। इसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरुनहा गांव निवासी श्याम नारायण सिंह (60) बाइक से ममहर बाजार से घर जा रहे थे। वे लटिया गांव के पास पहुंचे कि उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी मिलते ही परिवार के लोग भी पहुंच गए। उन्हें भदोही के एक निजी चिकित्सालय ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रभारी निरीक्षक राम सरीख गौतम ने बताया कि सूचना मिलने के बाद मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टपार्टम के लिए भेज दिया गया है।

भरत मिलाप मेले में युवक पर किया हमला, चार पर प्राथमिकी

औराई। बभनौटी के प्राचीन भरत मिलाप मेले के दौरान युवक पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। युवक की मां की शिकायत के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज करके जांच कर रही है। युवक की मां लीलाधरपुर निवासी सरिता देवी ने बताया कि उनका बेटा करन नौ अक्तूबर, 2025 को बभनौटी में होने वाले भरत मिलाप को देखने गया था। आरोप लगाया कि गांव के ही विपक्षी रामसागर, करण, जमंते और मुत्तन गांव की लड़कियों पर छींटाकशी करते थे। आरोप लगाया कि विपक्षियों ने मेले में उनके बेटे के सिर पर हमला कर दिया। इससे वह लहूलुहान हो गया। इसकी जानकारी परिवार वालों को हुई तो वे मौके पर पहुंचे और करन को अस्पताल पहुंचाया। आरोप लगाया कि विपक्षियों ने उनके बेटे की चेन छीन ली है। बताया कि मामले में कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई थी। सुनवाई न होने पर कोर्ट में गुहार लगाई गई। कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रभारी निरीक्षक अश्वनी त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है।

स्टेटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट सभी 6 केंद्रों पर पहुंचे, तैयारियों को परखा

भदोही, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड की ओर से 14 और 15 मार्च को होने वाली पुलिस भर्ती की परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए रिहर्सल बृहस्पतिवार को किया गया। विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज, नेशनल इंटर कॉलेज समेत अन्य सभी छह केंद्रों पर पहुंचे सेक्टर, स्टेटिक मजिस्ट्रेट सहित अन्य अधिकारियों–कर्मचारियों ने पूरी प्रक्रिया का रिहर्सल करते हुए तैयारियों का जायजा लिया।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक **देश की उपासना**

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।